हरियाणा विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में 24-6-81 को बाबू जी का आल इंडिया रेडियो रोहतक से प्रसारित अभिभाषण के अंश

भजन लाल वजारत को आज पूरे 2 साल हो गए है। हरियाणा की जनता को जितनी निराशा, अयोग्यता, भ्रष्टाचार विरोधियों व श्रमिकों का दमन और मंत्रीगण आश्वासन भंग का सामना इन दो सालों में करना पड़ा है, हरियाणा इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस सरकार की जानबूझकर चलाई गई अमीर परस्त तथा गरीबमार नीतियों से जनता को शका होने लगी है कि आया उनकी समस्यायों का समाधान प्रजाराज प्रणाली से हो सकेगा ?

वर्ष 1981-82 के बजट में 49 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया। घाटा इससे भी ज्यादा है, पर 49 करोड़ रूपये का घाटा भी हरियाणा के इतिहास में किसी बजट में नहीं हुआ। जो धनी व्यक्ति टैक्स देने योग्य है नपर टैक्स लगाने की बजाय, भजन लाल सरकार ने सत्ता में आने के तुरन्त बाद जुलाई, 1979 में रोड टैक्स आरडिनेंस को वापिस लेकर ऐसे कारखानों के मालिकों को लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना का लाभ पहुंचा दिया जो हरियाण की पवित्र धरती में फैक्ट्रीयां लगाकर हरियाणा से तम म सुविधाओं का लाभ लेते हैं परन्तु अपने केन्द्रीय कार्यालय हरियाणा से बाहर बनाकर हरियाणा को न केवल प्रान्तीय व केन्द्रीय बिक्री कर से वचित करते हैं बल्क उन पर लगे आय टैक्स के भाग से भी वचित रखा जाता है। बार-बार प्रयत्न करने के ब वजूद इन लोगों ने अपने केन्द्रीय कार्यालय हरियाणा में नहीं खोले। इनको काबू करने के लिए जब मैंने वर्ष 1979 का बजट पेश किया और इसका सुझाव दिया तो इस टैक्स के सिद्धांत को सर्व सम्मति से हरियणा विधान सभा ने स्वीकार किया था। 2 साल में हरियाणा खजाने को 4 करोड़ रुपए का नुकसान देकर इस साल के बजट भाषण में श्री खुर्शीद अहमद, वित्त मन्त्री को इसी टैक्स को कंसाइन्मेन्ट टैक्स के नाम पर लागू करने का सुझाव देना पड़ा। परन्तु टैक्स लागू फिर भी नहीं किया क्योंकि इसका प्रभाव धनी कारखानो पर ही पड़ने वाला था। यहीं नहीं, पिछले साल बिजली डयूटी घटाकर धनी कारखानेदारों को भजन लाल सरकार ने लगभग 3 करोड़ रुए सालाना की रियायत दी और उसके विपरीत गरीब बिजली उपभोक्ताओं पर घरेलू खपत पर कम से कम खर्चा 2 रुपए से 6 रु. और गरीब दूकानदार पर 5 रुपए से 21 रु. मासिक रेट कर दिया। आश्चर्य इस बात का है कि रोड़ टैक्स की वापिसी की और बिजली डयूटी दरों की कमी की मांग खले तौर पर किसी ने भी नहीं की थी।

भजन लाल सरकार ने कुछ दिनों के बाद ग्रामीण औद्योगिकरण की नीति को बदल दिया। देवी लाल जी के जमाने में ग्रामों में उद्योग लगाने पर जो सुविधाएं केवल ग्रामीण युवकों को मिलती थी अब उन शहरी लोगों को भी दी जाने लगी जो ग्रामों में उद्योग लगाएंगे। इसके परिणाम अवश्य ही होने थे कि ग्रामीण युवकों की बजाये सुविधाओं का लाभ धनी परिवारों के युवक ही उठाए। खेतों के लिए ट्यूबवैलों को बिजली देने में जो प्राथमिकता देवी लाल जी के मुख्य मन्त्री काल में दी जाती थी अब प्राथमिकता उद्योगों को दी जाने लगी। भजन लाल की भ्रष्ट और अमीर पस्त नीतियों के कारण सबसे पहले उनके अनुभवी साथी श्री रिज़क राम ने मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दिया और फिर फरीदाबाद में श्रमिकों पर अंधा-धुन्ध फायरिंग के कारण और न्यायिक जांच न कराने पर एक और अनुभवी मन्त्री स्वामी अग्निवेश ने त्याग पत्र दिया।

4. सबसे ज्यादा कमाल भजन लाल जी ने यह किया कि वह और उसके साथी जिस श्रीमती इन्दिरा गान्धी को पानी पी-पी कर दिसम्बर 1979 तक कोसते थे, जनवरी, 1980 में श्रीमती जी के प्रधान मन्त्री बन जाने पर थोक रूप में दल-बदल कर उसी की शरण में चले गए। सारा हरियाणा उस थोक दल बदल पर दंग रह गया। इसी कारण डा० मंगल सैन तथा श्रीमती कमला वर्मा जैसे अनुभवी मंत्रीगण जिन्होंने मंत्री पद की खातिर दल बदलने से इन्कार कर दिया था, मंत्री पद छोड़ गये। कांग्रेस सरकार के रुप में भजन लाल मंत्रिमण्डल ने जन विरोधी नीतियों और कामों को और भी तेज कर दिया। काम के बदले अनाज की स्कीम तथा प्रौढ़ शिक्षा स्कीम बिल्कुल ठप्प कर दी गई। लोगों की समस्य ओं से जुझने के बजाय मंत्रीमण्डल का ज्यादा समय सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण और स्थान-2 पर मील पत्थर रखने पर खर्च होने लगा। मगर जिला भिवानी और उसके निकट क्षेत्रों में कई साल से सूखा पड़ रहा है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

5. इसके अतिरिक्त जितने भी आश्वासन जन भलाई के कामों के बारे में विधान सभा में भिन्न-2 अवसरों पर दिए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। 1980 के बजट अधिवेशन में खुद मुख्यमंत्री ने मेरे सवाल पूछने पर कहा था कि हरियाणा में फैक्टरियों से जो गन्द निकलता है और उससे जो वातावरण दूषित होता है उसका समाधान 1 साल के अन्दर कर देंगे। सवा साल से अधिक हो गया है, इस भयानक समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पग नहीं उठाए गए। उठाया भी कैसे जाए धनी कारखानेदारों को काफी रुपया खर्च करना होगा, तभी यह समस्या हल होगी। उनसे रुपया कौन खर्च कराए ? जनता उनकी गन्दगी सड़ान्ध से बेशक मरती रहे। इसी प्रकार 1980 के बजट अधिवेशन में 2 मन्त्रियों ने सरकार की ओर से विश्वास दिलाया था कि राज्य में पंचायती राज कायम करने के लिए अगले सैशन तक विस्तारपूर्वक बिल पेश किया जाएगा। मगर आज तक ऐसा बिल पेश नहीं किया गया।

6. 1981 के बजट अधिवेशन में बात और स्पष्ट हो गई : भजन लाल की सरकार न शहरों और न ही ग्रामों में जनता को अधिकार देना चाहती है। इसीलिए नगरपालिकाओं के चुनाव का आश्वासन देकर उसे बार-बार भंग किया गया। पंचायत समितियों के चुनाव 6 माह के अन्दर कराने का आश्वासन भी पूरा न होगा। डबवाली बलात्कार, कत्ल और पुलिस फायरिंग पर न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन विधान सभा में दिया था परन्तु कई महीनों से रिपोर्ट आने के बावजूद कुछ भी नहीं किया गया। कलांवाली और नरवाना में सरकारी ठेकों पर जहरीली शराब बेचने से जितनी मौते हुई और आदमी अन्धे हुए इतने भयानक कांड किसी और राज्य में नही हुए और न ही हरियाणा में इससे पहले कभी हुए। गहराई से देखा जाए तो इन हत्याओं का कारण मुख्यमन्त्री की ओर से 7-7 80 को लिखा वह पत्र है जो सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को लिखा था कि ठेके पर डी. एस० पी० के पद से नीचे के अधिकारी तलाशियां न लें। पुलिस कर्मचारियों ने मुख्यमन्त्री का संकेत भलि प्रकार समझ लिया। शराब के ठेकेदार आबकारी विभाग के कर्मचारियों से पहले ही साठ-गांठ रखते थे अब वे पुलिस से भी निश्चिन्त हो गए। इसका परिणाम अवश्य होना था। कलांवाली और नरवाना में हुआ। आखिर मुख्य मन्त्री को अपना 7-7-80 का पत्र वापस लेना पड़ा।

7. स्वामी अग्निवेश जिसने भजन लाल को मुख्य मन्त्री बनने में पूरी सहायता दी थी, अब जब हरियाणा में बन्धवा लेबर की रिहायी के लिए प्रयत्न आरम्भ किया तो उनके साथ जो सलूक हुआ, किस तरह उनका सामान हरियाणा भवन दिल्ली से बाहर फेंका गया और उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई। इन सब बातों से हरियाणा निवासियों का सर शर्म के मारे झुक गया। आश्चर्य यह है कि मुख्यमन्त्री ने कांग्रेस (ई) के 20 सूत्री प्रोग्राम के एक महत्यपूर्ण मद बन्धवा लेबर की रिहाई के प्रोग्राम की भी धज्जियां उड़ादी।

8 भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है। किसी सत्ताधारी विधायकों या मन्त्रियों के विरूध भ्रष्टाचार की शिकायत की कोई भी जांच नहीं कराई जाती। श्री बलवन्त राय तायल और मुख्य मन्त्री के एक दूसरे के प्रति लगाए गए आरोपों और इसी प्रकार श्री सुरजेवाला व स्वामी आदित्यवेश तथा डा० सुखदेव और स० तारा सिंह, मन्त्री के एक दूसरे के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कोई जांच नहीं कराई गई। इस प्रकार जन जीवन और भी ज्यादा भ्रष्ट होता चला गया।

9. हरिजनों की भलाई का दावा करने वाली इस सरकार का यह हाल है कि 1979-80 के बजट में मैंने बतौर वित्त मन्त्री हरिजन चौपालो के लिये 96 लाख रुपये रखे थे परन्तु अढाई-तीन महीने बाद देवीलाल सरकार ने त्यागपत्र दिया तो भजनलाल सरकार यह सारी रकम 31-3-80 तक खर्च नहीं कर सकी। इ में लगभग 25 लाख रुपये बचा लिये गये और इतनी ही राशि यानि 25 लाख रुपये 1980-81 के बजट में रखी गयी। यह राशि भी 31-3-81 तक खर्च नहीं हुई और अब 1981-82 के बजट में हरिजन चौपालो के लिये केवल 5 लाख रुपये रखे गये हैं। इस से स्पष्ट है कि इस सरकार को हरिजनों और ग्रामीण लोगों से कितनी सहानुभूति है!

10. अन्त मे पिछले दो महीनों से सहकारी समितियों के ऋणियों पर जो दमन चक्र चलाया जा रहा है उसकी जितनी निन्दा की जाये उतनी थोड़ी है। सरकारी विभाग के कर्मचारी न केवल धारा 67 (ए) सरकारी समितियां एक्ट का उल्लंघन करते हैं किन्तु धारा 69 एक्ट माल और उसके अधीन बनाये गये नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हजारों गरीब ऋणियों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना गिरफ्तार करके मिनी बैंकों के दफ्तरों में बन्द रखा जाता है। सारे प्रान्त के ग्रामीण लोग सहकारी जीपों की दौड़ से उसी तरह

downloaded from modchandigarh.org

भयभीत है जिस तरह आपातकाल में नसबन्दी करने वाले लोगों से भयभीत थे। आश्चर्य यह है कि जो कारखानेदार हरियाणा वित्त निगम या अन्य कर्मशियल बैंकों से लाखों रुपये लेकर डकार गये, उनके विरुद्ध ऐसा कोई पग नहीं उठाया जाता। ग्रामीण लोगों को बैंकों आदि से जो ऋण ट्रेक्टर, थरैशर, ट्यूबवैल मोटर आदि के लिये दिया जाता है वह भी उन्हें सीधा नहीं दिया जाता बल्कि मन्जूर-शुदा दुकानदारों के द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें कम से कम 15-20 प्रतिशत अधिक दाम देने पड़ते हैं। ग्रामीण लोगों के साथ इस सौतेली मां जैसे वर्ताव को तो हटाने के लिये भजन लाल सरकार ने क्या कार्यवाही करनी थी उलटा उनकी गेहूं के जब 130 रुपये प्रति क्विन्टल से फालतू बिकने का अवसर आया तो किसानों को फालतू कीमत का लाभ दिलाने की बजाये ऐसे हालात पैदा कर दिये, जिस से फालतू दाम देने वाले ग्राहकों को मण्डियों से भागना पड़ा। भारत सरकार ने 130 रुपये प्रति क्विंटल के निचले दाम निश्चित किये थे न की ऊपर के दाम। भजन लाल सरकार की इस गलत नीति से हरियाणा के किसानों को कई करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इन्हीं सब बातों का परिणाम है कि भजन लाल सरकार को छवि आज जितनी कम है, उतनी कम किसी सरकार की भी नहीं थी। और अब गढ़वाल हलके में हरियाणा की पुलिस भेज कर तो रही सही सांख भी खतम कर ली। चुनाव आयोग को वह सारा चुनाव रद्द करना पड़ा। इन्हीं गलत कामो का परिणाम है कि लोक सभा के इन उप चुनाव में कहीं 75 प्रतिशत और कहीं 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मतदान जैसा कीमती अधिकार का भी प्रयोग नहीं किया। इस से ज्यादा शोचनीय हालात प्रजाराज प्रणाली मानने वालों के लिये और क्या हो सकते हैं।

आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता

(बाबू जी के विचार जो 'हरियाण तिलक' के विशेषांक में 27 जनवरी, 1981 को प्रकाशित हुए श्री जैन उस समय हरियाणा विधान सभा में विपक्षी नेता थे)

राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति एक पड़ाव था अन्तिम मन्जिल (लक्ष्य) नहीं था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बिना अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचना कठिन ही नहीं असभव था अन्तिम लक्ष्य है आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता। अर्थात सभी देशवासी आर्थिक दृष्टि से किसी अन्य देशवासी का दास न हो और सामाजिक दृष्टि से जन्म के आधार पर ऊंचे नीचे न समझे जावें।

स्वतन्त्रता संग्राम में लगे हुए कितने ही स्वतन्त्रता सेनानी यह समझते थे कि स्वतन्त्रता मिलने पर देश को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व गरीबी-अमीरी के फर्क जैसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। पर आश्चर्य है कि इन स्वतन्त्रता सेनानियों में से कितने सारे ऐसे थे जिनको यह आशा थी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उक्त समस्याए कुछ दिनों में स्वतन्त्र भारत की हकूमत ही हल कर लेगी और जनता को उसके लिए नया संघर्ष छेड़ने की जरूरत न होगी। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन्हीं स्वतन्त्रता सेनानियों में से जो लोग हकूमत में आये, विधायक बने या सदस्य लोकसभा या प्रान्तों व केन्द्र में मन्त्री बने, उनमें से प्रायः सभी ने राजनीतिक स्वतन्त्रता को पड़ाव नहीं मंजिल समझ लिया और मन्जिल पर पहुँचने पर यात्रियों का काफिला स्वाभाविक तौर पर जैसे आराम करना अपना अधिकार समझता है वैसे ही स्वतन्त्रता के बाद प्रायः इन मित्रों ने ऐसा समझा और अमल किया। बहुत कम सेनानी ऐसे थे जिनका यह विश्वास था और अब भी है कि आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की मन्जिल नये जन आन्दोलन के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि काफिला मंजिल भूल गया है और भारतीय नर-नारी प्राय राजनैतिक स्वतन्त्रता से प्राप्त फल को चखने में व्यस्त हो गए है। इसके अतिरिक्त यह जानना भी जरूरी है कि जैसे गुलामी के युग में हम अपने तमाम दुःखों का कारण ब्रिटिश साम्राज्य को समझते थे वैसे आज हमारी बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी, अत्याचार कमरतोड़ महगाई व गरीबी-अमीरी के फर्क का जिम्मेदार कौन है? इन बातों की तरफ जिन जिन देशवासियों का ध्यान जाएगा तो यही भारत की भयानक समस्यायें काँटे की तरह उनके दिलों में चुभने लग जाएंगी। और फिर यह भी निश्चय हो जाएगा कि इन सब समस्यायों की जिम्मेदारी सरमायेदारी अर्थ व्यवस्था है, तो इस सरमायेदारी ढांचे को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ कर देशवासी इस सरमायेदारी व्यवस्था के विरुद्ध नया आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की मन्जिल तक पहुँचने के लिये आवश्यक था और है कि एक दल सरमायेदारी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने वालों का बनता और विरोधी दल सरमायेदारी के हिमायतों का। बड़े सरमायेदार भारत में गिनती के हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। परन्तु सरमायेदाराना ज़हनीयत (विचारधारा) इन सरमायदारों के इलावा और बहुत लोगों की हो गई है।

सबसे पहले इस विचारधारा को बदलना है। मुझे यकीन है कि जितनी जल्दी भारत के बुद्धिजीवी और साधारण नागरिक इन बातों को समझेंगे कि भारत को आज की भयानक समस्यायें जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, सरमायेदारी व्यवस्था की उपज है और सरमायेदारी व्यवस्था को समाप्त या बदले बिना उनका समाधान नहीं हो सकता, उतनी जल्दी न केवल उनकी जहनीयत बदलेगी, अपितु वह सरमायेदारी ढांचे को बदलने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी और आन्दोलन के लिए तैयार होते जावेंगे। सरमायेदारी व्यवस्था को हटाने के लिए एक नए संग्राम की तैयारी करनी है।

downloaded from mdchandra.in.org